THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Yes, Sir. Cost-cum feasibility survey for electrification of Kharagpur-Waltair section of which Kharagpur-Khurda Road is a portion, has been sanctioned. The survey has been entrusted to General Manager, Central Organisation for Railway Electrification, Allahabad. Survey work is presently in progress and the same is expected to be completed and report submitted by September '93.

Decreasing number of Rhinos in the Kaziranga National Park in Assam

*320. SHRI BHADRESHWAR GOHAIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is gradual decrease of the Rhinos in the Kaziranga National Park in Assam;

(b) whether Government are aware that the officials are in league with the poachers in the regular killngs of Rhinos in Assam; and

(c) what steps have been taken by Government to prevent such killing and preserve these world famous species?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Rhino population in Kaziranga is reported to have declined from 1250 in 1989 to 1129 in 1991.

(b) No such report has been received from the State Government.

(c) Government continues to take measures to prevent poaching of all scheduled animals, including Rhinos, through increased patrolling of the Park and its surrounding areas, improved system of communication, building up of information network to know of poachers' activities, carrying out raids on suspected centres of trade in poached widlife products and creating a public awareness condusive to conservation of the Rhinos.

"वन क्षेत्र के विनाश को रोकने के लिये योजना"

2647. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय पौधे तथा अन्य छोटी-छोटी वनोपज देने वाले वन क्षेत्रों, जो तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं, के विनाश को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वर्ष 1989-90 के दौरान इस कार्य पर राज्यवार, कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) इस संबंध में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों, जो मुख्य रूप से लघु-वनोपजों और औषधीय पौधों से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या इन औषधीय पौधों तथा लघुवनोपजों के विकास हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :(क) भारत सरकार ने औषधीय पौधे और अन्य लघु वन उत्पाद की पैदावार वाले वन क्षेत्र के विनाश को रोकने के लिए तीन स्कीमें बनाई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास।

(2) अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार के कार्य में अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धन लोगों को शामिल करना।